Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 26-04-2007
Participants : Ganesan Shri L.,Salim Shri Mohammad,Yadav Prof. Ram Gopal,Tripathy Shri Braja Kishore,Dhindsa Shri Sukhdev Singh,Chandrappan Shri C.K.,Thomas Shri P.C.,Yadav Shri Devendra Prasad,Ponnuswamy Shri E.,Kuppusami Shri C.,Thangka Balu Shri K.V.,Yerrannaidu Shri Kinjarapu,Deo Shri V. Kishore Chandra S.,Gangwar Shri Santosh Kumar

Title: Regarding Supreme Court's judgement on 27 per cent reservation for OBCs in higher educational institutions.

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Mr. Speaker, Sir, in continuation of the fervent appeal made by our leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, in his letter dated 23rd April, 2007, and 02.04.2007 to the hon. Prime Minister, Madam Sonia Gandhi ji and the hon. Minister of Human Resource Development Thiru Arjun Singh ji, I would like to express our deep concern about the doubtful and non-implementation of the long felt need of 27 per cent reservation to the OBCs in higher education and that too after due process of legislation made by this august House unanimously.

As stated by my leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi in his letter dated 02.04.2007 to the Prime Minister, Madam Sonia Gandhi ji and Minister of Human Resource Development, the Central Government can proceed with the Notification of the various Castes which constitute the Backward Classes under Section 2 (g) of the Act based on the list of castes notified in pursuance of the Mandal Commission Report and the List notified by the respective State Governments as agreed by the Supreme Court in its order dated 29.03.2007.

In these circumstances, I demand that the Government should pursue the issue putting forth all its efforts to convince the judiciary so as to have an appropriate verdict on this long pending aspirations of people of OBCs in the country and to implement the 27 per cent reservation for OBCs in the Government institutions of higher education from this academic year itself without fail. [R5]

श्री संतोा गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष की सोच बहुत ही कैजुअल है, सामान्य व्यवहार है। हम बहुत अधिक कानूनी बात पर नहीं जाना चाहते। ओबीसी के छात्रों को जो सुविधा देने की बात हो रही है, अगर इस र्वा उन बच्चों को वह सुविधा नहीं मिलती है तो वास्तव में यह दुर्भाग्य होगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से ले ताकि आपस में कोई विवाद न हो। जो एक सही नीति तय हुई है, उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करें और यह संदेश यहां से न जाये कि हम बंटे हुए हैं। पूरा सदन इस विाय पर एक है, परन्तु दुर्भाग्य है कि जिस ढंग से न्यायालय में हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी, उस ढंग से हम नहीं रख पाये। हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र इसका फैसला किया जाये और इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता की ओर न जाकर राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से इस काम को लिया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि बच्चों का भविय खराब न हो और जो सुविधा देने की बात है, उस पर सरकार अपनी स्पट राय दे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस विाय पर आपने चर्चा की अनुमति दी है, वह काफी गंभीर है। दो माननीय न्यायमूर्ति की बैंच द्वारा जब से ओबीसी के 27 परसेंट आरक्षण पर रोक लगायी गयी है, तब से ओबीसी के करोड़ों लोगों के मन में आशंका व्याप्त हो गयी है। आप जानते हैं कि ओबीसी का 27 परसेंट आरक्षण सर्विस मेंनहीं है। यह रिजर्वेशन आपर्च्युनिटी है। जब र्वा 1992 में फैसला हुआ था, तो कहा गया था कि सर्विस में आप 27 परसेंट आरक्षण क्यों दे रहे हो? आप इन लोगों को कैपेबल बनाओ। आप उनको शिक्षा में आरक्षण दो। जब शिक्षा में, एडमिशन में, नामांकन में ओबीसी के लिए 27 परसेंट आरक्षण शुरू हो गया, तो इसको टाल दिया गया, रोक दिया गया। क्या नौ न्यायमूर्ति की बैंच के फैसले को दो न्यायमूर्ति की बैंच द्वारा पलट दिया जायेगा? ...(व्यवधान)

MR. SPEKAER: Mr. Devendra Prasad Yadav, you have made your point. Pleasedo not go into the details of the matter.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं, वह बहुत कैटेगरीकली औरसावधानीपूर्वक बोल रहा हूं। क्या यह नई परम्परा स्थापित हो रही है? देश में क्या दो जज की बैंच नौ जजों की बैंच के फैसले को पलट सकती है? ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not go into that. You have expressed your concern.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let us not go into it. The matter is before the court. You have said enough. You have expressed your concern.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आज देश मेंबहुत ही गंभीर परिस्थिति खड़ी है। माननीय सदस्य सरकार के बारे में कह रहे हैं, तो सरकार पहल कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार और आप न्यायपालिका, विधायिका के अधिकार ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let us wait. You have already expressed your concern.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सम्पूर्ण सदन ने जिस कानून को पारित कर दिया, उसमें क्या आपत्तिजनक है? सम्पूर्ण संसद के दायित्व को चुनौती दी गयी है, आज यह सवाल है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I request you not to make any reflection on the court. I will not allow that. Please don't record.

*(Interruptions) ...**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : संविधान के तहत यह कोई निर्णय नहीं है।क्या आप भारतीय संविधान पर नहीं बोलने देंगे? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम संविधान पर बोलने देंगे लेकिन न्यायपालिका पर नहीं बोलने देंगे।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : भारतीय संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार सीमांकित किये गये हैं। क्या एक उच्च संस्था दूसरी संस्था में हस्तक्षेप करेगी? ...(व्यवधान) आज यह तय करना है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Don't record it.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदय : आपने बोल दिया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक आप बोलने की इजाजत नहीं देंगे । ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने आपको बोलने के लिए कहा, तो आपने बोला है। Don't make any mention about the court's jurisdiction here. I will not allow that.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने कौन सी आपत्तिजनक बात बोली है। मैं एक भी आपत्तिजनक बात नहीं बोलना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओबीसी के लिए 27 परसेंट आरक्षण इंश्योर्ड कैसे होगा?

* Not recorded

महोदय, इस समय जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है, उसे इस सदन द्वारा कानून पारित किए जाने और संविधान में अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) के होते हुए भी रोक दिया गया है। यह इस सदन में सभी दलों की सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इस मामले पर यह सदन डिवाइडेड नहीं है। सर्वसम्मति से हाउस के द्वारा एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के लागू होने में जो व्यवधान है, उसे केन्द्र सरकार दूर करे। मैं आपसे भी इसके लिए अनुरोध करता हूँ क्योंकि आप इस लोकतांत्रिक संस्था के सर्वोच्च हैं।

MR. SPEAKER: Nice to hear that.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संविधान के तहत जो क्षेत्राधिकार रेखांकित किया गया है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: That we can discuss later.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभी उसके अनुरूप अपने-अपने क्षेत्राधिकार को समझें। ... *

MR. SPEAKER: It will not be recorded.

*(Interruptions) ...**

MR. SPEAKER: Nothing should go on record. I have called Shri Ganesan.

*(Interruptions) ...**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :... *

MR. SPEAKER: Nothing more, please.

*(Interruptions) ...**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) :... *

MR. SPEAKER: I will not allow this.

… (*Interruptions*)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :... *

* Not recorded

MR. SPEAKER: Mr. Yadav, I would not have allowed this matter to be raised as it is pending in the court, but because of the sentiments all across the House, I have allowed it. But you are misusing the opportunity I have given to you. Please do not refer to the judiciary.

… (*Interruptions*)

SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, yesterday also I had raised it in the All-Party Meeting. This is a very serious matter which we have taken into account… (*Interruptions*)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं सच बोल रहा हूँ, सच सुनने में कठिनाई होती है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You can discuss it in a proper manner.

SHRI L. GANESAN : Sir, since the Parliament has passed an Act unanimously, therefore, not only that the Supreme Court might have given any decision, but we should have to take into account the Parliament within its sphere. Parliament is the most powerful body and it has passed an Act to this effect. ... *(Not recorded)*

MR. SPEAKER: I will not allow that. Please do not misuse it. You must also respect the judiciary, as I believe that we are entitled to respect, they are also entitled to respect.

SHRI L. GANESAN : Sir, my submission is that as soon as the stay was granted, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has convened an all Party meeting there and passed a resolution to the effect that it should be reconsidered. Not only that, a *bandh* was observed there but it was also a total success.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written letters to the concerned people requesting them that it should be reconsidered and somehow or the other it should be passed. Once again, he has appealed to the Government of Tamil Nadu and also to Shrimati Sonia Gandhi and others to convene a Joint Session of the Parliament so that it should be discussed and it should be passed once again.

MR. SPEAKER: Md. Salim. Please, just refer the matter and do not refer to the courts.

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और जहां तक न्यायपालिका द्वारा दिए गए स्टे-आर्डर की बात है, मैं उस आधार पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब एकेडेमिक सेशन शुरू होता है उस समय IIMs और IITs में एडमिशन का यह मामला आ गया है और एक तरह की दुविधा बन गयी है। ऐसे में सरकार को इस सदन द्वारा पारित किए गए कानून के आधार पर अपना पक्ष अच्छी तरह रखना चाहिए और दूसरी तरफ यह कांफ्लिक्टिंग इंट्रेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे देश में आरक्षण के नाम पर एक हिस्से को दूसरे हिस्से को अलग करके लड़ाने की कोशिश की गयी है। हम सदन में जैसे एक साथ हैं, पूरे समाज में भी वही स्थिति पैदा होनी चाहिए। एडमिशन्स में इस समय यह जो रूकावट आई है, उससे बहुत से साधारण कैटेगरी के और पहले से ही रिजर्व कैटेगरी में आने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से एकेडेमिक इयर लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साथ ही रोजगार का भी साधन जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला ले और स्थिति को बेहतर बनाए।[R6]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह जो मसला है, यह 27 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण का पूरक है, सप्लीमेंट है। अगर पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़-लिख नहीं सकेंगे तो उनके लिए नौकरियों में जो 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है,

वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मूल चीज यह है कि उन्हें शिक्षित करके इस लायक बनाया जाए कि वे आगे चलकर नौकरी पा सकें। इसीलिए संसद ने सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन किया था। The unanimous will of the House is the will of the people. यह समझना चाहिए। मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। Sometimes a very peculiar situation arises before the country as well as the Parliament when the judgement of a larger Bench is overruled.

MR. SPEAKER: Please do not go into it. I know you have rightly expressed your concern.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाएं।

… (*Interruptions*)

प्रो. राम गोपाल यादव : इस मसले पर पूरा डिसकशन हो, इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से भी नोटिस दिया गया है। इसलिए इस पर चर्चा होना जरूरी है। चूंकि हम यहां न्यायपालिका का नाम नहीं ले सकते, तो फिर कुछ नहीं कह पाएंगे।

MR. SPEAKER: You have expressed your concern.

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से पैरवी होनी चाहिए ताकि जिन लाखों बच्चों का भविय दांव पर लगा हुआ है, वे उससे बच सकें।

MR. SPEAKER: Just express your concern on this issue. Let us not decide here about the court.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): I would not go into the details. I would like to only state that it was the unanimous decision of this House that the OBC students should be provided 27 per cent reservation in institutions of higher learning. By doing so, we are only enabling those students to have a brighter future in their lives. Now that has been thwarted by the decision of the Court. So, I would like that this matter should be thoroughly discussed by this House at the earliest and I hope you may take necessary steps.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Hon. Speaker, Sir, now thousands of students are going with uncertainty. This House gave full support, unanimous support and full mandate to the Government in favour of this Constitutional amendment. We are quite hopeful that from this academic year, OBC students will get admission in AIIMS and other institutions of higher education. I had an opportunity to go through the written argument of the Government. I should say, through you, to the entire House that it was placed in so poor light in some of the arguments. Even we are not convinced how the Government with such full support is not placing the points seriously before the court which may convince the court. I would request the Government to again go through the written argument and place it properly – the entire House desires it; the country desires it – before the court; they should get permission from the court so that OBC students may be permitted to get admission from this academic year.

MR. SPEAKER: Let us hope for the best. Now the matter will be heard on 8th. I am sure, the sentiments expressed will be duly noted.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (PARVATIPURAM): Mr. Speaker, Sir, I rise to join my colleagues with respect to the sentiments they have expressed regarding the 27 per cent reservation to students belonging to backward classes.

Whatever has been said in this House is actually a reflection of the public opinion. We all know and we must appreciate the fact that public opinion is the lifeblood of democracy. As has been mentioned by my colleagues earlier, this was a decision taken by the Government after a complete consensus was reached with the support from Members from all sides of this House. Today our main concern is that those students who will be beneficiaries of this particular enactment should not be sufferers as far as this academic year is concerned. While in deference to your wishes I shall not express anything that has happened in the Court because we have always held courts in a high esteem; I also wish that the Government should resolve this and also ensure that such conflicts do not take place in future.

SHRI K.V. THANGKABALU : Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

MR. SPEAKER: Please be brief.

SHRI K.V. THANGKABALU : Sir, as my learned colleagues have expressed the concern, the UPA under the leadership of Madam Sonia Gandhi and also all the leaders of this House unanimously supported this issue. We passed this Bill and it became a law. When it became a law, we thought that the entire OBC will get their due share in their journey of education. Sir, without education no society can develop, and particularly the weaker sections. The weaker sections of this country wanted education.

Sir, you have told us not to say anything about the Court. Today, the issue has come. I am not repeating anything. Sir, under your leadership, the Parliament passed this Bill and the whole country applauded it. Even then, we are not able to get ...* It means that we are in a precarious condition.

---

* Not recorded

MR. SPEAKER: You can say, the law is not being enforced. Please strike out that word.

SHRI K.V. THANGKABALU : The point now is whether Parliament is supreme or not. This issue has arisen today.

Sir, in your wisdom, you have already called an All-Party Meeting and all the Parties are supporting this issue. When all the Parties and the entire 100 crore people of the country are with you and with the Government, today's happenings are not good for the country. We need the law of the country to be protected. First of all, the supremacy of Parliament is to be protected. The entire people are representing the whole country. This is a very serious issue. We want OBCs to get the due share and the majority community should get their due share … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Well, I believe, a view has been fully expressed …

SHRI K.V. THANGKABALU : Sir, we are with you. We want this issue to be sorted out without any loss of time.

MR. SPEAKER: This is the agony of the Speaker. He cannot say one word. I have now to take permission from all of you to say one word!

SHRI K.V. THANGKABALU : No, Sir. We are with you. We want your support and see that this issue is sorted out.

MR. SPEAKER: That is what I am saying. I was going to support you. The will of the House was expressed in the unanimous passing of this Bill.

SHRI K.V. THANGKABALU : Not only that, the will of the House should be supreme and it should sustain also.

MR. SPEAKER: Now, Shri Kinjarapu Yerrannaidu.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir, after sixty years of our Independence, we have given 27 per cent reservation to the OBCs in the higher educational institutions in the country. This Bill was passed in both the Houses of Parliament after arriving at a consensus. At this stage, the Government of India should intervene, argue properly on 8th May in the Supreme Court and see that the reservation is implemented from this academic year. If there is any obstacle, a Joint Session of both the Houses should be convened and also if there is any need we have to amend the Constitution. At any cost we have to provide reservation for OBCs in the educational institutions from this academic year.

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, इस विाय के बारे में मेरा मत थोड़ा भिन्न है और दो बिन्दुओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहला बिंदु है, कोर्ट की 9 जजों की बैंच ने कहा है कि क्रीमी लेयर को इसमें शामिल न किया जाए। दूसरा बिंदु है, उन्होंने कहा है कि कुछ परसेंट, जो इक्नामिकली वीकर सैक्शन हैं, जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों संसद और सरकार इस बात को अपनी प्रैस्टीज का सवाल बना रही है? जो इक्नोमिकली वीकर सैक्शन हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन का फायदा क्यों न मिले? मैं समझता हूं कि इस विाय पर डिस्कशन होना चाहिए और हमें दोबारा सोचना चाहिए।

MR. SPEAKER: The law has been very clear.

Now, Shri E. Ponnuswamy.

SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

I do not want to repeat anything which has already been spoken by my esteemed colleagues. Our Party's stand is that the law passed unanimously by both the Houses of Parliament should be immediately implemented from this academic year. So, I would request the Government to do the needful to emphatically impress upon the Judiciary, to convince them to just implement the Act immediately.

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, on behalf of the Kerala Congress Party, I would also strongly urge that the will of the people, which is supreme should be emphasized again in the Parliament, if necessary. But I would submit that though the judicial scrutiny may be possible and it is coming on the way, I do not comment on them.

But I would submit that whatever has to be done even to take it again from whatever interpretation which has come, has to be done by this Parliament, and the Government has to take it up with all seriousness. The Government has got full support in this matter.